Power Sector Reforms

*310. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether all the State Governments have implemented power sector reforms;

(b) if not, how many States are yet to implement these reforms; and

(c) how the reforms have improved the power sector performance in the States which have implemented the reforms?

THE MINISTER OF POWER (SHRI ANANT GANGARAM GEETE): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) No, Sir.

26 States have signed Memorandum of Understanding (MoU) with the Government of India, reflecting a joint commitment of the Centre and the States for undertaking power sector reforms in a time-bound manner. The remaining States are yet to sign MoUs to reflect their commitment for undertaking reforms.

(c) It is too early for making an assessment of the impact of the implementation of reforms.

श्री सुरेश पचौरी: सभापति महोदय, ऐसे अनेक राज्य के स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं जो घाटे में चल रहे हैं। बल्कि मैं यह कहूं तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि प्राय: सभी राज्यों के स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड घाटे में चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को मध्य प्रदेश को 80 करोड़ रुपये प्रतिमाह देना पड़ रहा है। जो पावर की अवेलेबिलिटी है तथा जो कंजम्पशन है, उसमें काफी गैप है। उस गैप को पूरा करने के लिए जो पावर सैक्टर रिफार्म्स आप बना रहे हैं, उस दिशा में मध्य प्रदेश को ध्यान में रखते हुए आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं?

श्री अनन्त गंगाराम गीते: सभापति जी, सदस्य ने जो चिंता यहां पर जताई है, वह सत्य है। लगभग 30 हजार करोड़ का घाटा है और सारे राज्य विद्युत बोर्ड इस घाटे में हैं। यह जो घाटा राज्य विद्युत बोर्डों को हो रहा है, उसका मुख्य कारण है, वितरण क्षेत्र में जो कमियां हैं और जिन सुधारों की आवश्यकता वितरण के क्षेत्र में है... हम समय-समय पर उन सुधारों को नहीं कर पाए, इसलिए सारे राज्य विद्युत बोर्ड आज घाटे में चल रहे हैं। केंद्र सरकार ने इस घाटे को

कम करने के लिए साथ ही साथ जो आम उपभोक्ता है, उसको समय पर बिजली मिले और अच्छी बिजली मिले, इसके लिए राज्यों को सुधार कार्यक्रम अपनाने के लिए कहा है। सारे राज्य धीरे-धीरे इन सुधारों को अपना रहे हैं। उसमें स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमीशन का गठन करना है। उसके तहत जो मीटरिंग करनी है, शत-प्रतिशत मीटरिंग करनी है, चोरी को रोकना है और चोरी को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने हैं, इस प्रकार के कई उपाय हैं जो सुधार कार्यक्रमों के तहत हम कर रहे हैं। राज्यों की ओर से धीरे-धीरे उन कार्यक्रमों को भी अच्छी सहायता हो रही है।

Mr. Chairman: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Demining in forward areas

*301. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in the forward areas our forces are engaged in clearing mines without the aid of demining sets and mine boots;

(b) if so, the number of Jawans killed and injured so far during the demining process; and

(c) the steps proposed to be taken to stop manual demining to save human lives as well as complete the demining process quickly?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) to (c) No, Sir. Demining equipment, anti-mine boots and other protective gear are available with our troops, who are engaged in demining operations in the forward areas, where land mines were laid during OPERATION PARAKARAM. Nevertheless, during the current demining operations, from October, 2002 upto 6th March, 2003, five Army personnel were killed and fifty-nine were injured.

Manual demining is an inescapable part of the demining process along with other methods, and thus cannot altogether be dispensed with. However, to ensure safety in demining operations, only trained army personnel who laid the mines and were familiar with the terrain, have been employed in recovery of the mines.